RAJYA SABHA

Wednesday, the 17th August, 1988/ *26,* Sravana 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Purchase of pollution control vessel for Bombay Port Trust

281. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) when was the decision to put-chase a pollution control vessel for Bombay Port Trust taken;

(b) what steps have so far been taken to implement this decision; and

(c) by .when the vessel is likely to be purchased and start functioning?

THE MNISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) No decision has been taken on the purchase of a pollution control vessel fo'r Bombay Port Trust. After reviewing the specifications proposed by Bombay Port Trust they were advised to invite fresh tenders. Bombay Port Trust has subseque'ntely proposed that the vessel be procured with assistance from Asian Development Bank.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, 1984 में बम्बई पत्तन न्यास ने पदूषण नियंत्रण जलयान खरीदने का प्रस्ताव किया । 85 में कुछ समय के लिए जलयान किराये पर लिया गया । विश्व से टेंडर निमंत्रित किये गये । 86 में टेंडर खोले गये । परकार को सिफारिशें भेज दी गयीं । 87 में फिर नये प्रस्ताव बने और 88 में बम्बई पत्तन न्यास को फिर से नये टेंडर बुलाने की सलाह दी गयी । भगवान जाने बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और हमारी सरकार के बीच का यह सिलसिला 21वीं सदी तक शायद चलता रहे । इन चार वर्षों में एक ओर बम्बई बन्दरगाह में पदूषण बढ़ता रहा और दूसरी ओर पदूषण नियंत्रण जहाज की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ती रही । इस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह चार वर्ष की जो अक्षम देरी हुई है जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ा और जलयान की कीमत भी बढ़ी उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? पिछले टेंडर्स में ऐसी क्या कमियां थीं जिनके कारण नये टेंडर्स बुलाने के लिए बम्बई पत्तन न्यास को कहा गया ?

श्री राजेश पायलट : सर, पहले तो शुरुआत में सदन को मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें देरी हुई इसमें कोई दो राय नहीं हैं । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इसमें इतनी देरी हुई है उसके कारणात ऐसे रहे । जब पिछली बार प्रोपोजल बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने हमें भेजा 24 अक्तूबर, 1986 को उसके लिए वैलिडिटी डेट 30 अक्तूबर, 1986 थी । 6 दिन का टाइम मिनिस्टरी के पास था । 6 दिन में फैसला नहीं कर पाये क्योंकि जो उन्होंने टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन इस वैसल्स को प्रोक्योर करने के लिए भेजा था वह ठीक नहीं था । हम लोगों ने उनसे कहा आप दुबारा टेंडर्स मंगा लीजिए और नये स्पेसिफिकेशन भी मंगाइये । अगर मैं सारी बातें डेटवाइज दूं तो बहुत टाइम लग जायेगा । मैं यह बात मानता हूं कि इसमें देरी हुई और देरी के कारणात दोनों तरफ से थे । ऐसा पहला अपनी किस्म का एन्टी पोल्यूशन वैसल दुनिया में बनाया गया इसलिए बहुत ज्यादा प्रिकाशंस सरकार की तरफ से रहे और फारेन एक्सचेंज भी इन्वाल्व था : तो पहले तो मैं यह बताऊंगा कि जो भी देरी हुई उसका कारण यह था कि दोनों तरफ टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन में डिफरेन्स चलता रहा और अब जो आज की स्टेज है वह यह है कि 1987 में उन्होंने फैसला किया कि हम फारेन एक्सचेंज के बतौर अपने रिसोर्सेज करें और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो टोटल पैकेज है उसमें इंक्लेड कर दिया है । आज जब मैं इस मामले को आफिसर्स के साथ डिसकश कर रहा था और हम उसमें डिलेज के कारण देख रहे थे तो उसमें दो बातें थीं । पहली बात तो यह थी कि पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन को फाइनेंशियल पावर्स करीब डेढ़ करोड़

रखी हुई थी। डेढ़ करोड़ से ऊपर के जितने भी प्रोपोजल होते थे वे सब मिनिस्ट्री में आते थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले यह फैसला ले लिया गया है कि चार करोड़ तक के जो प्रोपोजल्स होंगे उनके बारे में पोर्ट ट्रस्ट अपने आप फैसला करेगा। इससे यह सुविधा हुई कि ऐसे केसेज में पोर्ट ट्रस्ट अपनी फाइनेंशियल पावर्स में सक्षम होकर फैसला कर सकेगा। डिसकशन में यह बात भी कही गई कि यह वेशल बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है और वहां के एन्टी पोल्यूशन के लिए इसकी जरूरत है क्योंकि वहां पर हमारी जो फेसिलिटीज हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि ए०डी० बी० से डिलिंक करके अपने रिसोर्सेस से जो उन्हें चार करोड़ तक की पावर्स दी गई हैं उससे समस्या आसान हो जाएगी। इसकी कास्ट 3.4 करोड़ के करीब है और मुझे उम्मीद है कि इसमें जल्दी कदम उठा पाएंगे। मैं एक बात माननीय सदस्य को बता दूं कि इसमें देरी जरूर हुई है और उस देरी को सुधारने के लिए हमने कदम उठाये हैं और आगे भी उठाएंगे।

श्री सभापति: क्या आपका फैसला पक्का है, फाइनेंस को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है?

श्री राजेश पायलट: हमने उनको चार करोड़ की पावर्स दे दी हैं और इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, माननीय मंत्री जी देरी मान रहे है इसके लिए उन्हें धन्यावाद देता हूं और मैं उनके इरादे पर विश्वास भी करता हूं। लेकिन इनके मंत्रालय में नौकरशाह इतने हावी हैं कि मैंने जलयान के बारे में पूछा था, लेकिन फिर भी मंत्री महोदय ने यह कहा कि चार करोड़ तक की खर्च की अनुमति दे दी गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि बम्बई पत्तन न्यास की ओर से एक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट डौक वर्कर्स के लिए बन रहा है, उसका आर्किटेक्ट नियुक्त करने के लिए पांच लाख की अनुमति नौ महीने से मंत्रालय में पड़ी है, इस निर्णय के बाद भी अभी तक अनुमति नहीं मिली है। जहां तक पैसे की बात है, यह बिल्कुल बेकार बात है क्योंकि चार वर्ष तक आप देर करेंगे तो आपके पास पैसे बचेंगे नहीं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बम्बई पोर्ट ट्रस्ट से सलाह कर किसी ज्योत्सना होल्डिंग को पकड़े और फिर सरकार की ओर से चलाएं और जल्दी से नियंत्रण करें अथवा दो टूक शब्दों में यह कहे ... **(व्यवधान)**

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, this is not proper. This is totally improper linking something to something else. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let us stick to the point please. *(Interruptions)*

SHRI A. G. KULKARNI: How *is* Jyotsna Holdings concerned with this? Hon. Member should know what to ask, where to ask and when to ask.

SHRI VIRENDRA VERMA; It will be decided by the Chairman, not by you and me.

श्री सभापति: आप काम की बात करें, इस तरह से आपस में झगड़ा करेंगे तो टाइम नष्ट हो जाएगा। अब आप सवाल कीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, मैंने पूछने की जो शिक्षा ली है वह अप्पा साहब से जब वे इधर थे, ली है। अब वे इधर से उधर चले गये **(व्यवधान)**

श्री सभापति : अप्पा साहब इधर-उधर नहीं गये हैं। उनकी परफोरमेंस मैं देख रहा हूं। आप महाराष्ट्र के झगड़े को यहां मत लाइये।

श्री प्रमोद महाजन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने यह प्रदूषण नियंत्रण जलयान खरीदने के लिए कोई समयावधि निश्चित की है? यह जो चार वर्ष की देर हुई है इसको देखते हुए क्या आपने कोई निश्चित समयावधि तय की है जिसके अन्दर आप इसको खरीद लेंगे और इस बन्दरगाह के प्रदूषण को दूर करेंगे?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, मैंने बहुत साफ लफ्जों में बात कही है और जो सही बात है उसको सदन में रखा है। मुझे खास दुख है कि माननीय सदस्य इस मामले को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे किसी चीज को लेकर भी कोई टेस्ट कर लें, उनको खुली छुट्टी है। वे जहां कहीं भी गलती को पकड़ सकते हैं, यह ओपन चेलेंज की बात नहीं है। कोई दूसरी बात आप दिमाग में न रखें। लेकिन जहां तक वैसिल की बात है, एंटी पौल्यूशन के बारे में मैंने कहा कि बंबई पोर्ट एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है और हम वहां पौल्यूशन से चिंतित हैं। वहां अभी भी बहुत फैसिलिटीज हैं और हम लोगों ने एंटी पौल्यूशन मेजर्स लेने के लिए और भी कदम उठाए हैं। इसलिए इस जरूरत को देखते हुए बहुत जल्द-से-जल्द वैसिल को एक्वायर किया जाएगा। एक्जैक्ट टाइम देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है और वैसिल की एलेबिलिटी होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: You try to expedite it as much as possible.

SHRI RAJESH PILOT; We will try to expedite it as early as possible.

श्री जसवंत सिंह : फाइल आउट ट्रे में चली गई है।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Is it a fact that the Bombay Port area and the waterfront around Bombay Port have become a dumping ground by foreign ships passing the port or ships awaiting loading....

MR, CHAIRMAN: The question is about a pollution control ship. You stick to the point. This does not come strictly under it. This is about the purchase of a pollution control vessel. Whether there is pollution or not is not 'relevant.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Sir, this is to save the Bombay Port from pollution.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, he is very near to the point.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I am very close to the point. Sir.

MR. CHAIRMAN: You must be to the point. In supplementaries you cannot stray about.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH; Part (a) of my supplementary iiS, till you acquire the ship, the danger is so big to the city of Bombay. Because it will take time, what other steps are you taking to cleans the port and to ensure that the passing and waiting ships do not add to pollution?

Part (b) of my question is very important. Ig it. a fact that the Department of Environment has served a notice on the Bombay Port Trust to adhere to 'the basic anti-pollution measures or face closure of many of its activities? Particularly they have mentioned oil spillage.

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, आपकी इजाजत से जिस क्वेश्चन को महाजन जी ने रखा है कि इंस्टीट्यूट को सेंक्शन नहीं मिली है वह गलत है। सेंक्शन मिल चुकी है। दूसरी बात जो बम्बई पोर्ट के बारे में माननीय सदस्य ने पूछी है, बंबई में we have a cell called the Pollution Control Cell, headed by a Director of Pollution Control, which was created in 1983. We have at the moment equipment dedicated like oil-cum-solid waste recove'ry vessels. We are also going in for Russian type steamer for dock basins. The steps required to control are—inspection of ships and waterfront area to ensure that ships do not create pollution; ships are required to comply with Marpole Convention on amount of smoke from the funnel. Sir, there are various steps which I can read out. But I would like to inform the House and the hon. Member that we have gone very strict on anti-pollution measures. Earlier the penalty was roughly Rs. 500

or so for anti-pollution action of any ship, which has been increased to Rs. 5 lakh, so that people know that if they go for pollution, they will be fined heaviiy. So Government is taking very strict steps in this direction,

MR. CHAIRMAN; You also personally visit Bombay Port some time.

SHRI RAJESH PILOT: I have been visiting. Sir.

MR. CHAIRMAN: The conditions are so bad if you go from the sir port that you feel what it is.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV-, Sir, You must be aware of the fact that in a very posh area like Nariman Point when people go for a walk and breathe air, they realise what type of pollution is there in Bombay.

श्री सभापति : मैंने बोल दिया ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, my question is, the hon. Minister has already stated that he has started the procedure for tha purchase of such a ship, may I know from where the tenders have been called—whethe'r they are foreign tenders or national tenders? If they are foreign tenders, it will take much more time. So what type of tenders have been called? Secondly, is thero any technology available in our country, so that we can build such type of vessels? Because-it is not a question of Bombay Port alone; the other ports also will get benefit of that. So what progress is theres in this matter?

SHRI RAJESH PILOT: Sir, as I have mentioned, for the vessel in question, there were 15 tenders—11 from foreign firms and 4 from our own country. If we are going in for this vessel, which is one of the best in the world, then it has got to be foreign. It is a Russian make vessel. In regard to final decision, I have just said that I have discussed with the officials. This is the most important step that we must go in for. I am not in a position to toll today whether it will be totally indigenous or foreign.

MR. CHAIRMAN: Shri Kulkarni

श्री जसवंत सिंह : शायद भूल गये (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, my friend, Mr Jaswant Singh

श्री सभापति : आप अपनी दोस्ती बाहर करिये सेंट्रल हाल में । हाऊस को चलने दो (व्यवधान) सवाल पूछ लीजिये ।

SHRI A. G. KULKARNI; In a parliamentary form, when there rre many side questions asked, it is the duty____ (Interruptions)

श्री सभापति आप अपने सवाल पर आइये । छींटाकशी मत कीजिये । (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: I am really surprised that even Jaswant-

श्री सभापति : भूल जाइये अपने को (व्यवधान) आपकी और उनकी उम्र में कितना फर्क है (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: The point is, Mr. Rajesh Pilot replied so that many questions will not arise at all. He has correctly replied. My question is on a different plane(Interruptions) ....

Anyway, you are going to take the Russian vessel for anti-pollution measures. But the pollution is increasing because of many factors. The unloading of the ships is delayed. There is no mechanization. That is why many vessels are staggered in that very small area of Bombay Port So, is this aspect also being consi dered by the Ministry so that the pollution could be reduced even otherwise?

SHRI RAJESH PILOT: Sir, he is very tight. This is also one of the factors. Normally we have "collectors" to collect oil and other things which are discharged while a ship is waiting for berthing. With all these facto'rs in mind we are coming out with a comprehensive plan for each port. Some measures have already laeen taken in some ports, and in some they are in the process. It is a continuity; it cannot be just one day's work.

MR. CHAIRMAN: They want that there should not be a long wait.

SHRI A. G. KULKARNI; Is it a comprehensive plan for Bombay Port alone or for other ports also?

SHRI RAJESH PILOT: For all ports. Each individual port will have a separate plan. If the honourable Member is keen about Bombay Port, I can tell him what comprehensive plan we have for the Bombay Port.

SHRI KAMAL MORARKA; Sir, about the Bombay Port Trust, the honourable Minister has said that the powers of its Chairman have been extended and purchases up tO Rs. 4 crores can be handled locally. . I want to know whether these purchases will also cover, apart from pollution control equipment, certain other things which have been pending for a long time—about which I have written tO the Minister also—like the contaitteri-zation programme and othe'r things which are pending at the Ministry level. Does this decentralization *of* power include a host of other things which can expedite decision-making in Bombay or is it limited to purchase of certain types of equipment only?

SHRI RAJESH PILOT: I think I could not make myself clear to the honourable Member. I said that the financial powers of the Chairman of Bombay Port ' Trust have been enhanced so that he could take decision and action up to Rs. 4 crores. That includes everything, even the projects which are in the Port. The Port Trust can take decisions up to Rs. 4 crores. So, that will cover what all you have meant.

Operation Blackboard for Prin Schools

282. SHRI LAL K. ADVANI;
SHRI ASHWANI KUMAR :-t

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) when was the Operation Blackboard for primary schools approved and what facilities were proposed to be included in the scheme;

(b) what is the Statewise number of such schools which have been provided with these facilities so far and what is the feed back about the continuation and utilisation of the facilities; and

(c) what targets have been fixed for the year 1988-89, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

fa) The scheme of Operation Blackboard, which was finalised in May 1987, envisages provision, in a phased manner for all primary schools, which had been established by 30-9-1986, of the following facilities;

(i) two reasonably large rooms usable in all weather;

† The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashwani Kumar.